यह तो कपूर कमीशन ने नहीं कहा है। उन्होंने यही कहा है कि जब जानकारी प्राप्त हुई तो तहकीकात या जांच करने में कोई कमी रही या क्या करना चाहिए था इम पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। इमी मंबंध में तीन अफमरों का नाम उन्होंने विशेष लिया है और उन्हों के संबंध में जांच और कार्यवाही हो रही है। उन मे से एक अफसर तो अब दुनिया में रहे नहीं और दो के खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

## गैर-बंगला भाषी लोगो की पूर्वी पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ

+

## \*213. श्री जगन्नाथराव जोशी: श्री जदेजा: श्री निहारल/स्कर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

- (क) क्या इस वर्ष मार्च, अप्रैल और मई के महीनो में पूर्वी बंगाल से आये शरणाधियों में से बहुत से गैर-बंगला भाषी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया था; और
- (ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT): (a) and (b). The facts are being ascertained from the State Governments concerned.

श्री जगगना बराब जोशी: अध्यक्ष महोदय, यदि इसी तरह के जवाब मिलेगे कि तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं तो सवाल पूछने का फिर मतलब क्या रहा ? सेरा कहना यह है कि कम से कम ऐसी स्थिति में जानकारी पूरी होने पर ही उत्तर दिया जाय ताकि हम सप्लीमेंट्री पूछ सकें। हमें मालूम है कि मंत्री महोदय क्षेक्चंस को टालना चाहते हैं क्योंकि बाद में वह सदन के पटल पर मारी जानकारी रखेंगे भी तो हम उस पर सप्लीमेंट्री नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ निर्देश दीजिए कि जानकारी पूरी होने पर उत्तर दें जिस में सप्लीमेंट्री हम पूछ सकें।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: They get ten clear days' notice. Still, if they do not get the information, I do not know what we are to do.

SHRI S. M. BANERJEE: Kindly allow us to ask some supplementary questions at least.

MR. SPEAKER: There is no reply. How can there be supplementary questions now?

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मैं जानना चाहता हूं कि अप्रैल महीने में जो...

अध्यक्ष महोदय . उन के पास रिएलाः कोई नही है। आप प्रश्न करके क्या करेंगे ?

श्री जगन्नाथ राव जोशी अाप कम सं कम ऐसा निर्देश तो दे दे कि आगे ऐसा उत्तर न दिया करें...(व्यवधान)

श्री हुकम जन्द कछव य: सरकार को 21 दिन का समय हम देते है फिर भी वह जानकारी नहीं दे सकते ।

अध्यक्ष महोबय: हमारी तो जो प्रैंक्टिम है लोक मभा की हम तो रख देते हैं उस पीरियड के बाद। उनकी तरफ में जवाब न आग्रे तो उस का हमारे पास क्या इलाज है ?

SHRI S. M. BANERJEE: May I have your guidance in this matter?.....

SHRI INDRAJIT GUPTA: What is the point in giving ten days' notice? I hat much of time is given just for collecting the information.

श्री कृष्ण चंद्र पंत : मैं माननीय नदस्य में निवेदन करूंगा कि जो स्थिति जमीन पर है

उस पर भी जरा गौर करें। कितने लोग वहां आ गए हैं, कितने शरणार्थी आए, कितने रोज बहां आ रहे हैं, इस बक्त सारा ध्यान इस पर केन्द्रित है कि कैसे उन की व्यवस्था की जाय? यह प्रश्न कि कितने बंगला बोलने वाले थे, कितने गैर बंगला बोलने वाले थे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मवाल तो स्पष्ट है।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : गवाल तो बड़ा स्पष्ट हपर मैं आप की सेवा में यही तो निवेदन कर रहा हं कि राज्य सरकारों का ध्यान इस वक्त उस व्यवस्था में लगा है कि कै से उनको रिलीफ पहचाई जाय और अगर ऐसी रिथान में राज्य सरकार हम को कोई तथ्य नहीं भेजें तो यह वात कुछ समझ में आती है। लेकिन हम ने तो उन को लिखा है कि वह ये तथ्य जल्दी से जल्दी भेजें और वह जैसे ही भेजेंगे हम सदन के पटल पर रख देंगे।

श्री जगन्नाथ राव जोशी: हम सवाल करते है तो जानकारी के लिए करते है। में यहता ह कि दो दिन ज्यादा ले लें लेकिन भवाल का जवाब तो आना चाहिए जिस से हम जान-कारी हासिल कर सकें। आप एसा कुछ निर्देश तो दे मकते है।

MR. SPEAKER: He should make a statement sometime later.

श्री हकम चन्द कछवाय : बड़े दुख की बात है कि यह सवाल 7 नारीख को दिया गया था और इस पर भी सरकार की तरफ से जानकारी नहीं आई।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: They are evading.

## Export of Iron Ore to Japan

\*215. SHRI S. R. DAMANI: the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state:

- (a) the quantity of iron ore committed for shipment to Japan in 1970-71 against the long-term contracts and how much was actually shipped;
- (b) in case of short supplies what are the reasons; and
- (c) whether it resulted in penalties for delayed shipments or non-fulfilment according to the terms of the contracts and, if so, the loss sustained thereby ?

THE MINISTER OF **FOREIGN** TRADE (SHRI L. N. MISHRA): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

(c) Under the terms of the concerned contracts, there is no penalty for short delivery of quantity and hence there was no loss on this account.

## Statement

Taking the various contracts together, a total quantity of 10.34 million tonnes of iron ore was to be shipped to Japan during the financial year 1970-71, compared to which the total shipments were 8.24 million tonnes. Of the consequent shortfall of 2'10 million tonnes, about half was on account of the production shortfall in the Bailadilla mine. The rest of the shortfall was due to various causes, prominent amongst which were the strike in Madras Port in April last year, the prolonged strike in Calcutta Port later in the same year, and fall in the railway movement of Barajamda ore towards Paradeep Post and Calcutta about the middle of last year.

SHR1 S. R. DAMANI: I specifically asked how much quantity has been exported against long term contracts. But in the statement all are combined together. I want a specific answer to my specific question.

SHRI L. N. MISHRA: statement, we have mentioned that taking the various contracts together including longterm contracts, a total quantity of 10:34 million tonnes of iron ore were to be shipped to Japan during the financial year 1970-71 as against which the total shipments were 8.24 million tonnes, leaving a shortfall of about 2.10 million tonnes. I accept there has been a shortfall.